फार्म फॉरवर्ड

वर्ष-1, अंक-2ः अक्तूबर 2024

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

Farm Forward

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

जायका मिशन ने टिकाऊ कृषि प्रणालियों का लिया जायजा

पालमपुर। जायका मुख्यालय मिशन के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को परियोजना क्षेत्र का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 में चल रही नई कृषि पद्धतियों की समीक्षा की। पिछले दो वर्षों में जायका कृषि परियोजना-2 क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय मिशन का यह पांचवां दौरा है।

इस दल के सदस्यों में सुश्री शिनो काटो, ताकाहिरो कोइके (दोनों जायका मुख्यालय के प्रतिनिधि), केन कुनीडा और सुश्री युकारी इनागाकी (दोनों जायका इंडिया से) शामिल हैं। जायका मिशन दल का हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय में स्वागत किया गया। मिशन दल ने कुलपति डॉ. नवीन ठाकुर, जायका कृषि परियोजना-2 के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। जायका कृषि परियोजना-2 के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने विस्तृत जानकारी दी और समीक्षा दल को प्रगति की स्थिति रिपोर्ट सौंपी।

जायका मिशन प्रतिनिधिमंडल ने पपरोला में संग्रह केंद्र का दौरा किया और लाभार्थी किसान उत्पादक कंपनी और इसके स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने गणमान्य व्यक्तियों को बताया कि केंद्र की स्थापना 2017 में परियोजना-1 अवधि के दौरान 36.77 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ की गई थी। बाद में, परियोजना-2 के दौरान जून 2023 में केंद्र को मौजूदा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)-बैजनाथ प्रगतिशील किसान उत्पादक निर्माता कंपनी लि. को सौंप दिया गया। पीएफओ की स्थापना पिछले साल 19 मार्च को जिला कांगड़ा के थारू (पपरोला) गांव में कार्यालय के साथ की गई थी। यह एफपीओ कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री, संग्रह ग्रेडिंग और ऊन, दूध संग्रह, बोतलबंद और बिक्री के प्रसंस्करण में काम कर रहा है। इसके 450 सदस्य हैं और गबली कूहल, हरटाडा, रग्लू, धरेर, छू नाला और बड़ाग्राम प्रगतिशील किसान उत्पादक निर्माता कंपनी लि. को सौंप दिया गया। पीएफओ की स्थापना पिछले साल 19 मार्च को जिला कांगड़ा के थारू (पपरोला) गांव में कार्यालय के साथ की गई थी। यह एफपीओ कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र (एससीटीसी) का भी दौरा किया, जिसे जापान की याट्स कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था। टीम के सदस्यों ने केंद्र के कर्मचारियों और शिटाके उत्पादकों के साथ बातचीत की। परियोजना के चरण-1 के दौरान राज्य फार्म विश्वविद्यालय परिसर में 3.25 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया। जबकि जायका कृषि परियोजना-2 अवधि के 9 वर्षों में 5.9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र के बारे में बताते हुए डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि यह केंद्र भारत में एक मॉडल के रूप में अपनी तरह का एक केंद्र है, और लकड़ी के ब्लॉकों पर शिटाके मशरूम उगाना शुरू कर दिया है। इस साल अगस्त के अंत तक 53.57 किलोग्राम सूखे मशरूम का उत्पादन किया गया। स्थानीय स्तर पर 65.575 किलोग्राम ताजा शिटाके मशरूम बेचे गये हैं। केंद्र ने तैयार ब्लॉकों के साथ-साथ ताजे और सूखे शिटाके मशरूम बेचकर 3.31 लाख का राजस्व अर्जित किया है। अप्रैल, 2023 में शिटाके मशरूम खेती की तकनीक को मानकीकृत करने के बाद, केंद्र ने 212 और 199 किसानों को शिटाके की खेती और प्रसंस्करण क्रमशः कुशल बनाने के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केंद्र ने विभिन्न स्थानों पर किसानों को 2675 परीक्षण ब्लॉक वितरित किए हैं। इस मौके पर परियोजना के कांगड़ा जिले के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे।

जायका टीम 4-5 नंवबर को प्रोजेक्ट क्षेत्र में

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, टोक्यो और इंडिया के प्रतिनिधि ''डिजिटल सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर'' प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने व परियोजना में सिंचाई योजनाओ को देखने के लिए 4 और 5 नवंबर को हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं।

जायका कृषि परियोजना-2 और जायका की डीएक्स लैब के सहयोग से संचालित इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधे बाजार से जोड़ कर उनकी आय में वृद्धि करना है। नगदी फसलों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस पर केंद्रित यह योजना किसानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और बाजार पहुंच को विस्तारित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम को परियोजना द्वारा अभी दो जिलों (मण्डी व सोलन) में शुरू करके इसकी पहल की है। इसकी समीक्षा करने के लिए 4 नवंबर को, जायका प्रतिनिधिमंडल मंडी जिले के ढ़ावण स्थित सिंचाई योजना की समीक्षा करेगा। इस सिंचाई योजना में देहात डिजिटल पार्टनर के रूप में काम कर रहा है जिसकी समीक्षा करने उपरोक्त टीम आ रही है।

देहात के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सलाह, लाइव मंडी दरों और बाजार जानकारी तक पहुंच मिल रही है, जिससे उनके उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं, जहां वे उन स्थानीय किसानों से संवाद करेंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपनी फसलें बेच रहे हैं। 5 नवंबर को जायका टीम हमीरपुर में जायका कृषि परियोजना-2 के मुख्यालय का दौरा कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। जायका टीम किसानों की आय पर डिजिटल मार्केट प्लेस के प्रभाव, संग्रह केंद्रों और लॉजिस्टिक्स की प्रभावशीलता तथा लक्षित 1500-2000 किसानों के लिंक का मूल्यांकन करेगी। यह दौरा जायका की डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हिमाचल प्रदेश में नवाचार और स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करता है।

मिशन ने संध कूहल कृषक विकास संघ को सौंपी

कांगड़ा। जायका मिशन प्रतिनिधिमंडल ने दूसरे चरण में संचालित की जा रही हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना की प्रगति समीक्षा को प्रवाह सिंचाई योजना संध कूहल का दौरा किया। कृषक विकास संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिनिधिमंडल ने लाभार्थियों को उपकरण सौंपे। किसानों से बातचीत की और सिंचाई योजना का बारीकी से निरीक्षण भी किया। कुल 28.91 लाख रुपये की इस योजना से 13.76 हेक्टेयर खेती वाले कमांद क्षेत्र के 107 किसान परिवारों को लाभ मिला है। कृषक विकास संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद ने प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया। जायका मिशन टीम के सदस्यों में सुश्री शिनो काटो, ताकाहिरो कोइके (दोनों जाइका मुख्यालय के प्रतिनिधि), केन कुनीडा और सुश्री युकारी इनागाकी (दोनों जाइका इंडिया से) शामिल हैं। जायका मुख्यालय के प्रतिनिधि ताकाहिरो कोइके ने दूध और सब्जी संग्रह ई-वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने अपने संबोधन में उपस्थित जनसमूह से कहा कि यह हिल फार्म ग्रुप के सहयोग से अनूठी पहल है। धर्मशाला के हिल फार्म ग्रुप ने धौलाधार मिल्क ब्रांड के तहत दूध के लिए एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह विस्तार जायका कृषि परियोजना के साथ सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जो एक पारस्परिक सहयोग की लाभकारी व्यवस्था प्रस्तुत करता है और किसानों के लिए कृषि बाजार पहुंच बढ़ाएगा। जायका मिशन टीम ने औपचारिक दीप जलाकर हल्दी के प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र को भी चालू किया। हल्दी प्रसंस्करण केंद्र का संचालन किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) द्वारा भद्रू संग्रह केंद्र, भवारना में किया जाता है। जायका मिशन के प्रतिनिधिमंडल ने भद्रू में एक खुदरा दुकान का दौरा किया, जिसमें चंबा-कांगड़ा जनजातीय शहद, जड़ें, फूल और उत्पादकों और विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह सहित स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि एचपीसीडीपी चरण एक अवधि के दौरान स्थापित यह रिटेल आउटलेट, जिसे हाइब्रिड रिटेल आउटलेट के नाम से जाना जाता है, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के उत्पादों के विपणन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पारंपरिक बिक्री के साथ ऑनलाइन बिक्री को एकीकृत करके कृषि उत्पादों का विस्तार करता है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को क्षेत्रीय और दूरदराज के उपभोक्ताओं दोनों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह मॉडल स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को अपने ग्राहक आधार में विविधता लाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और भौतिक और डिजिटल खुदरा समाधानों के संयोजन के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता का समर्थन करने में सक्षम बनाता है।

डॉ. चौहान ने दौरे के दौरान एफपीओ, एसएचजी, केवीए और किसान परिवारों के विविध लाभार्थियों और परियोजना स्टाफ का जायका मिशन प्रतिनिधिमंडल द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद किया।

श्री ताकाहिरो कोइके ने जायका मिशन प्रतिनिधिमंडल की ओर से जायका कृषि परियोजना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों और गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया।

हिन्दी मासिक ई-पत्रिका का विमोचन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 की मासिक हिंदी ई-पत्रिका 'फार्म फॉरवर्ड' का विमोचन दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 को परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान के द्वारा किया गया तथा इस ई-पत्रिका को सोशल मीडिया में अपलोड किया।

इस मौके में डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि यह मासिक ई-पत्रिका परियोजना के अगामी कार्य को जनता और किसानों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम होगा। यह प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण नवाचारों, उपलब्धियों और सफलताओं को भी उजागर करेगा। इस पत्रिका में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, कृषि सचिव डॉ. एस. पॉलरसु, परियोजना के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर और वरिष्ठ सलाहकार बलजीत संधू ने भी अपने शुभ संदेश भेजे।

ई-वैन को दिखाई हरी झंडी

जेंडर सेंसिटाइजेशन पर चार दिवसीय कार्यशालाएं संपन्न

सोलन, हमीरपुर, मंडी और पालमपुर के परियोजना क्षेत्रों में हुई कार्यशालाएं

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) द्वारा जेंडर सेंसिटाइजेशन पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सोलन, हमीरपुर, मंडी और पालमपुर के जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों में आयोजित की गई।

इस चार दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास में जेंडर समानता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना था। कार्यशाला के दौरान, जेंडर आधारित भेदभाव और इसके प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें यह बताया गया कि कैसे महिलाओं की कृषि क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी न केवल समाज के लिए, बल्कि पूरे कृषि तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को समान अवसर प्रदान कर, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सकेगी।

इसके अलावा, इस कार्यशाला में यह भी समझाया गया कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिबद्धता और योगदान को मान्यता देने के साथ-साथ उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी शामिल करना चाहिए। कार्यशाला ने उन तरीकों पर जोर दिया जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें कृषि के हर पहलू में सशक्त बनाने के लिए अपनाए जा सकते हैं।

हमीरपुर में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर आयोजित कार्यशाला

कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां और उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों को यह सिखाया गया कि जेंडर असमानता के कारण क्या हैं, इसके क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं, और इससे निपटने के व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं।

इन सत्रों में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे एक समावेशी कार्यसंस्कृति का निर्माण किया जा सकता है, जो सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। महिला किसानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में यह भी बताया गया कि महिलाओं को कृषि उत्पादन, विपणन और प्रबंधन के हर स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, जिससे न केवल उनकी स्थिति मजबूत हो, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी लाभ हो।

कार्यशाला में भाग लेने वाले विभिन्न (पीएमयू) के प्रतिभागियों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह कार्यशाला न केवल लिंग समानता की समझ को गहराई से बढ़ाती है, बल्कि इसे लागू करने के व्यावहारिक तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम माना जो कृषि विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस चार दिवसीय कार्यशाला से यह उम्मीद की जा रही है कि इससे हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र में जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रति एक सकारात्मक बदलाव आएगा। कार्यशाला का प्रभाव यह होगा कि एक भेदभाव-रहित और सशक्त वातावरण का निर्माण होगा, जो राज्य की समग्र कृषि प्रगति में सहायक सिद्ध होगा।

इसके अलावा, यह कार्यशाला कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। महिला कर्मचारियों की लिंग संवेदनशीलता को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 में विशेष पहल की गई है। इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों और कार्यस्थलों पर समान अवसरों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। कार्यशाला में उन्हें जेंडर आधारित भेदभाव और कार्यस्थल पर समावेशिता के महत्व के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह एक सकारात्मक कार्यसंस्कृति का निर्माण कर सकें। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रथाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि वह नेतृत्व की भूमिकाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। इस प्रकार के प्रयास न केवल महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र में लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

जायका कृषि प्रोजेक्ट के सोलन क्षेत्र की कृषि विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

सोलन। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन ने हाल ही में जायका परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जून 2021 में आरंभ हुई इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और कृषि विकास में सुधार करना है। इस परियोजना के तहत, सोलन, नाहन और रामपुर खंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों में आधारभूत संरचना का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन ने आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाते हुए 10 उप-परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्माण कार्य पूरा किया है। इस दौरान 54 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं, 39 टेंडर जारी किए गए हैं और 29 उप-परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है। एक परियोजना कृषक विकास संगठन (केवीए) को सौंप दी गई है, जिसका खेती योग्य कमांद क्षेत्र 5.44 हेक्टेयर है। इस उप-परियोजना की कुल लागत रुपए 18,86,517 है, जिससे 55 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 55 केवीए का गठन किया गया है, जिनमें से 47 पंजीकृत हो चुकी हैं। यह संगठन किसानों को एकजुट होकर कार्य करने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायता प्रदान कर रहे हैं। सभी उप-परियोजनाओं में बेसलाइन सर्वे भी चल रहा है, जो 46 केवीए में पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के आधार पर सभी उप-परियोजनाओं के लिए एक योजना बनाई जा रही है, जिसे उपपरियोजना विकास योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में उप-परियोजना की मूल जानकारी, उनकी फसलों उपज और भविष्य में उगाई जाने वाली नई फसलों का विवरण शामिल है। अब तक, 39 योजनाएं खंड परियोजना प्रबंधन स्तर पर तैयार की गई हैं, जो किसानों की कृषि गतिविधियों को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने में मदद करेंगी। किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए जिला और खंड परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कैंपों और परिचायक दौरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 403 प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन किया गया है, जिनमें 14,790 किसानों ने लाभ उठाया है। यह प्रशिक्षण कैंप किसानों को नई कृषि तकनीकों, प्रबंधन कौशल और बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन द्वारा उप-परियोजनाओं में नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें किसान सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये नाटक कृषि संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा हैं। आने वाले समय में, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके फसल विविधिकरण को सफल बनाके किसानों की आय को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य रहेगा।

हमीरपुर क्षेत्र में कृषि की विकासशील पहल

हमीरपुर। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में कृषि सुधार और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस परियोजना के तहत कुल 54 उप-परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो 749.84 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इन उप-परियोजनाओं का वितरण तीन खंड परियोजना इकाइयों के माध्यम से किया गया है, जिनमें हमीरपुर में 19, बिलासपुर में 16 और ऊना में 19 उप-परियोजनाओं का कार्य जारी है। अब तक 50 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से 37 को परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इनमें से 23 परियोजनाओं का कार्य आवंटित कर दिया गया है। इनमें से 18 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तक 51 उप-परियोजनाओं के लिए घर-घर सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और विभिन्न जागरूकता बैठकों के माध्यम से समुदाय को परियोजना के बारे में जानकारी देकर 50 कृषक विकास संघ गठित किए गए हैं। इसके पश्चात, किसानों के साथ गहन परामर्श के बाद 46 उप-परियोजनाओं के लिए उप-परियोजना विकास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें वर्तमान और प्रस्तावित फसल पैटर्न सहित सभी परियोजना की जानकारी सम्मिलित है।परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कृषक सहायता गतिविधियों पर प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। अब तक तीनों खण्ड परियोजना इकाइयों में कुल 295 एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 13,603 किसानों ने भाग लिया है।

'शैप कार्यक्रम' से किसानों को मिली नई दिशा

हमीरपुर। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) पूरे विश्व में छोटे किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए फसल पैदा करने से पहले मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को उनका हथियार बनाने के लिए योजना चला रही है जिसको कि शैप (स्मॉलहोल्डर हॉर्टिकल्चर एंपावरमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट) कहा जाता है । हिमाचल प्रदेश में ''हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2'' के अंतर्गत जायका के ओडीए लोन के माध्यम से 28 गांवों के किसानों को इस अप्रोच के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित करके सुदृढ़ करना है ताकि यहां के किसान फसल उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार करें। किसान स्थानीय और बड़ी मार्केट की मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण फसलें उगाएं ताकि उन्हें बेहतर फसल का भाव मिल सके और उत्पादन की बाज़ारीकरण के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार के किसानों के सशक्तिकरण करने के लिए यह अप्रोच चलाई जा रही है। परियोजना में हालांकी 28 गांवों को लक्षित किया गया है, लेकिन परियोजना के अधिकारियों ने अपने स्तर पर यह निर्णय लिया है कि हम सभी 296 परियोजना के लक्षित गांवों में सभी किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करके उनकी आमदनी की बढ़ोतरी को सुनिश्चित करके परियोजना के फसल विविधीकरण के उद्देश्य को अच्छे व प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या विभिन्न कार्यक्रमों के ऊपर परियोजना द्वारा जिला में पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका प्रदेश और प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। यह परियोजना न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, बल्कि क्षेत्र में किए गए निवेश का भी अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर रही है। जायका इंडिया के कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम को आईसी नेट नामक कंपनी के माध्यम से समर्थन मिल रहा है।

परियोजना निदेशक, डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि हमें प्रत्येक प्रशिक्षित अधिकारी से अपेक्षा है की वे शैप गतिविधियों के कार्यान्वयन में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सभी शैप गतिविधियों को आपस में समन्वित करें, जिससे संसाधन मानचित्रण, परियोजना चयन मानदंड और अन्य गतिविधियों की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। हमारा उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और बाजार की मांग के अनुसार अपने कार्य को अनुकूलित कर सकें।

हिमाचल प्रदेश में कृषि उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रतिनिधि का नाम	स्थापना का वर्ष	मुख्य उत्पाद	वार्षिक कारोबार	ईमेल आईडी
1.	अमृत धारा मिल्क प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, दाड़लाघाट	सुश्री रेणु ठाकुर, सीईओ	2015	दूध	1.5 करोड़	theamritdharadarlaghat@gmail.com
2.	चंडी माता अनारदाना सब्जी उत्पादन कंपनी विपणन सोसायटी लिमिटेड, दाड़लाघाट	श्री संतोष शर्मा, सीईओ	2016	सब्जियां	2 करोड़	chandifpo2015@gmail.com
3.	प्रगति वेजिटेबल्स एंड फ्लावर ग्रोवर एंड मार्केटिंग कॉप. सोसायटी, सोलन	श्री जोगिंदर, सदस्य बोर्ड और श्री दया राम,	2015	सब्जियां	1.25 करोड	hpicsw@gmail.com
4.	सिरमौर लहसुन, सिरमौर	श्री अनिल राणा, निदेशक	2014	लहसुन और अदरक	40 लाख	suryasirmour@gmail.com, sirmouragri@gmail.com
5.	हिल फार्म (धौलाधार मिल्क), कांगड़ा	श्री विकास सरीन, सीईओ	2021	दूध और कृषि उत्पाद	2.5 करोड़	Sareen.vikas@gmail.com, Sareen@shreedhara.in
6.	सैंधर एग्रो मार्केटिंग को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, सिरमौर	श्री हिम्मत सिंह अत्री, सीईओ	2020	लहसुन और अदरक	6.5 लाख	Attri.himmat@gmail.com
7.	चूरेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नाहन	श्री वीरेंद्र कपूर, सीईओ	2016	लहसुन और अदरक	10 लाख	Kapoornhn@gmail.com
8.	किन्नौर कैलाश एग्रो फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, किन्नौर	श्री ललित मोहन, सीईओ	2021	बागवानी फसलें	1 करोड़	negilalit422@gmail.com
9.	बैजनाथ प्रगतिशील उत्पादक कंपनी लिमिटेड, कांगड़ा	श्री अक्षय जसरोटिया, अध्यक्ष	2023	गेहूं का आटा, चावल	12 लाख	jasrotia72@gmail.com
10.	चंबा कांगड़ा ट्राइबल हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	श्री कुनाल				kunalsingh.t@hotmail.com
11.	समग्र हिमालय एफपीसी लिमिटेड	श्री मोहम्मद रियाज	2021	सब्जियां, अनाज, जड़ी बूटी	1.2 करोड़	
12.	धौलाधार पीर पंजाल एफपीसी लिमिटेड	श्री रजत, एमडी और श्री प्रिंस ठाकुर, निदेशक	2022	मक्की	15 करोड़	

स्त्रोत : एसपीएमयू, एफपीओ वर्कशॉप

जायका कृषि परियोजना और खाद्य सुरक्षा

विश्व खाद्य दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि हम हिमाचल प्रदेश के किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रणाली की ओर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से सशक्त करें। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (एचपीसीडीपी) का उद्देश्य किसानों को परंपरागत फसलों से आगे बढ़ाकर सब्जियों, फलों और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती में प्रशिक्षित करना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और राज्य में पौष्टिक आहार की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। परियोजना का लक्ष्य न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि किसानों की समृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है।

परियोजना के किसानों के समृद्धि के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह परियोजना युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें नई कृषि तकनीकों और आधुनिक कृषि प्रणाली से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में सहभागी बन सके।

हमारा उद्देश्य एक सतत कृषि प्रणाली का निर्माण करना है, जिसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके। यह मॉडल न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत बनेगा। इस विश्व खाद्य दिवस पर, आइए हम सभी मिलकर ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य करें जिसमें हर परिवार खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ उठा सके और हमारा प्रदेश इस दिशा में एक आदर्श राज्य बने।

बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार

हमीरपुर। 2030 तक भूख, खाद्य असुरक्षा और किसी भी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। हालांकि, यह लक्ष्य बढ़ते संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की स्थितियों, साथ ही खाद्य असुरक्षित और कमजोर क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के कारण अपनी प्राप्ति से दूर होता जा रहा है।

खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का मुख्य कारण स्वस्थ आहार तक पहुंच न होना और उसकी महंगाई है।

खाद्य सुरक्षा केवल भूख मिटाने से नहीं, बल्कि पौष्टिक और संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ी है। इसके लिए हमें एक ऐसे वितरण तंत्र की आवश्यकता है जो हर नागरिक को सस्ती और पौष्टिक खाद्य सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करे।

खरीदने की क्षमता का अभाव वैश्विक भूख का आकलन दिखाता है कि 'भूख मुक्त दुनिया' के लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई खास प्रगति नहीं हो रही है। 2023 में 9.4 प्रतिशत या 757 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे। अफ्रीका में भूख का स्तर 20.4 प्रतिशत है, जबकि एशिया में यह 8.1 प्रतिशत है। हाल के अनुमान बताते हैं कि 2030 तक, दुनिया के आधे भूखे लोग अफ्रीका में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की दर अधिक है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत कम है।

भूख और खाद्य असुरक्षा का गहरा संबंध लोगों की पर्याप्त भोजन खरीदने की क्षमता से है। 2022 में स्वस्थ आहार की औसत लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.96 डॉलर थी। हालांकि, कई निम्न-आय वाले देशों में अब भी स्वस्थ आहार तक पहुंच संभव नहीं है।

भारत में खाद्य असुरक्षा और असंतुलित आहार

भारत में आहार आम तौर पर अस्वास्थ्यकर और असंतुलित होते हैं। अधिकांश भारतीय आबादी पौष्टिक आहार तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। यहां आहार की गुणवत्ता और पोषण के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यह देखा गया है कि भारत के उच्च आय वर्ग के लोग भी पर्याप्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते, बल्कि प्रसंस्कृत भोजन का अधिक उपयोग करते हैं।

भारत के संदर्भ में, ''थालीनोमिक्स'' के अनुसार, पौष्टिक भोजन को सभी के लिए सुलभ और सस्ता बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए खाद्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी वर्गों के लोग स्वस्थ आहार का उपभोग कर सकें।

वैश्विक भूख सूचकांक और भारत की स्थिति

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में भारत की खराब स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि, (जीएचआई) के कुछ घटक कुपोषण और बाल मृत्यु दर से जुड़े होते हैं। भूख की समस्या इससे कहीं अधिक व्यापक है और इसे केवल भोजन की उपलब्धता से हल नहीं किया जा सकता। भारतीय सांख्यिकी संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 32 प्रतिशत भारतीय आबादी प्रति दिन न्यूनतम एक संपूर्ण भोजन तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

''भोजन का अधिकार'' इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का प्रमुख विषय है, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। भारत, जो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने पर गर्व करता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पूरी आबादी खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सके।

खाद्य बैंकों और खाद्य संग्रहण एवं वितरण तंत्र की स्थापना द्वारा भोजन की बर्बादी को रोककर भूखमुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। यह समय की आवश्यकता है कि हम भोजन की बर्बादी को हतोत्साहित करें और भूखमुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें।

विश्व खाद्य दिवस के इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परियोजना किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर सब्जियों, फलों और अन्य उच्च-मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है बल्कि पौष्टिक आहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। फसल विविधीकरण और उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से, एचपीसीडीपी राज्य के किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अधिक लाभकारी बाजारों से जुड़ने का अवसर दे रही है। यह पहल राज्य को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाते हुए हर नागरिक के लिए पौष्टिक और सस्ता आहार सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

जायका कृषि परियोजना की चार दिवसीय 'फॉलो अप रिव्यू मीटिंग'

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना-2 के अंतर्गत हमीरपुर स्थित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में ''पीएमयू स्टाफ के फॉलो अप रिव्यू मीटिंग'' का चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत परियोजना के निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने की, जिसमें मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर और वरिष्ठ सलाहकार बलजीत संधू भी उपस्थित रहे। यह बैठक जिला परियोजना प्रबंधक इकाइयों सोलन, हमीरपुर, पालमपुर और मंडी के लिए आयोजित की गई।

डॉ. चौहान ने बैठक के दौरान बताया कि अब तक 280 उप-परियोजनाओं का सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं। इनमें से 150 उप-परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 22 उप-परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 9 उप-परियोजनाओं को कृषक विकास संघ को सौंपा गया है। इसके अलावा, 13 उप-परियोजनाओं को जल्द ही सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

परियोजना निदेशक ने कृषि प्रसार अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करें, ताकि किसानों और अधिकारियों के बीच कोई अंतर न रहे। उन्होंने कहा कि जितना अधिक आप किसानों के बीच में रहेंगे, उतना ही बेहतर आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से करने की आवश्यकता पर जोर दिया और परियोजना की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया।

डॉ. चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर गतिविधि को रणनीति के तहत योजना बनाकर, कार्यान्वित करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि हम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हों। उनका यह संदेश अधिकारियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन था कि प्रत्येक गतिविधि को सुनियोजित तरीके से संचालित करना आवश्यक है, जिससे कि सभी हितधारक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। कार्यक्रम में वित्त अधिकारी, उप परियोजना निदेशक, जिला परियोजना प्रबंधक, विषय विशेषज्ञ और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के किसानों को आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्लग ट्रे में करें स्वस्थ नर्सरी तैयार

(क) मिट्टी रहित सामग्री :

कोकोपीट, वर्मीकुलाईट, परलाइट (3:1:1), प्लग ट्रे, बीज (किसी भी सब्जी का), सींचने का कनस्तर/फव्वारा

(ख) मिश्रण/मीडिया तैयार करना और भरना :

1. प्लास्टिक की तरपाल पर आवश्यकता अनुसार उपरोक्त, सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं ।

2. प्लग ट्रे को मिश्रण / मीडिया से भरें।

3. प्लग ट्रे के सेल/खानों को तैयार मिश्रण से लगभग एक तिहाई भरें।

सुझाव: ट्रे का चुनाव बीज के आकार पर निर्भर करता है। छोटे व्यास वाले बीजों को छोटे सेल/खाने वाले प्लग ट्रे में बोएं, और बड़े बीज को बड़े खाने वाली प्लग ट्रे में बोएं।

(ग) बीजाई और सिंचाई:

1. प्लग ट्रे के सेल/खाने में एक या दो बीज बोएं।

सावधानी: बीज को सेल के मध्य में रखना चाहिए, ताकि जड़ें सही विकास प्राप्त कर सकें।

2. बोए गए बीजों को अच्छी तरह से सड़े-गले गोबर या उपरोक्त मिश्रण/मीडिया से ढक दें। बीजाई के बाद, ट्रे की सतह को अखबार या कपड़े से ढक दें।

3. ट्रे को ढकने के तुरंत बाद फव्वारे से सिंचाई करें।

सावधानी: प्राय: जाली या सूती कपड़े को ट्रे पर रखने के बाद सिंचाई करनी चाहिए। बीज के ऊपर सीधा पानी डालने से बोया हुआ बीज बह सकता है। अगर जरूरत के अनुसार सिंचाई करें।

(घ) ट्रे में तैयार नर्सरी की सुरक्षा:

1. प्लग ट्रे को पॉलीहॉउस या लो पॉली टनल के अंदर या खुले में रखें।

सुझाव: प्लग ट्रे को पॉलीहॉउस या पॉली टनल के अंदर रखकर पौध को हम ठण्ड से बचा सकते हैं और बाहर की अपेक्षा अंदर के उच्च तापमान के कारण पौधों का विकास अधिक तेजी से होता है जिससे कि नर्सरी शीघ्र तैयार हो जाती है।

सुझाव: गर्मी के मौसम में, पॉली हाउस के अंदर के तापमान को कम करने के लिए शेड नेट (छायादार जाली) का उपयोग करें या लो-टनल का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

सावधानी: जड़ वृद्धि को प्लग ट्रे में बढ़ावा देने के लिए, प्लग ट्रे को बोर्ड या प्लास्टिक के तिरपाल/शीट पर रखें ।

(ङ) उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा और रोपाई:

उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा:

1. यदि पौध को, अधिक समय तक (30-40 दिनों तक) प्लग ट्रे में रखना हो तो उर्वरक का पत्तों पर छिड़काव (Foliar Spray) करें ।

सुझाव: एनपीके19:19:19, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम का छिड़काव करें।

रोपाई:

1. इस विधि से उगाई गई पौध 3-4 वास्तविक पत्तियों की अवस्था में या पौधे की 10-15 सें.मी. की ऊंचाई पर, रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी ।

2. रोपाई हमेशा शाम के समय में करनी चाहिए।

स्त्रोत :- टीसीपी

कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने प्रोजेक्ट किसानों को दिये पुरस्कार

ज्वाली। कृषि विभाग द्वारा जिला कांगड़ा के ज्वाली में किसान मेला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री प्रो.चंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना की जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर और खंड परियोजना प्रबंधन इकाई ज्वाली द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को कृषि मंत्री ने पुरस्कृत किया, जिसमें परियोजना क्षेत्र की हारत स्थित गोधन स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा पूर्णिमा देवी, गुनेहर के कृषक विकास संघ के सचिव और बैजनाथ किसान उत्पादक कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्य विचित्र सिंह को सम्मानित किया। इन दोनों को 5000-5000 रुपए की सम्मान राशि भी दी गई। इस मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में जागरूक करना था, जिससे उनकी आय और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। कृषि मंत्री ने किसानों की मेहनत को पहचान देने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऐसे पुरस्कार न केवल किसानों को प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य किसानों को भी कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करेंगे। कुल मिलाकर, इस मेले ने किसानों के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया, जहां वे एकत्र होकर अपने अनुभव साझा कर सके, जिससे कृषि विकास में नए उन्नति के रास्ते खुलेंगे।

लाहौल घाटी की जायका सिंचाई योजना का निरीक्षण

कुल्लू। दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 को हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधक इकाई कुल्लू द्वारा लाहौल घाटी के जोबरंग में बन रही सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया गया। खंड परियोजना प्रबंधक गोपाल चंद भारद्वाज ने कृषक विकास संघ, जोबरंग के प्रतिनिधियों एवं सिंचाई परियोजना के लाभार्थियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर उन्हें निर्देश दिए गए कि शेष कार्य को सर्दियों से पहले पूरा करें। निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों से निर्माण कार्य की नियमित निगरानी का भी आग्रह किया गया। इस मौके पर खंड परियोजना प्रबंधन इकाई के अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

गौरतलब है कि इस सिंचाई परियोजना से 228 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसका कमांद क्षेत्र 55.66 हेक्टेयर है। लगभग 1 करोड़ 32 लाख की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा में सुधार आएगा।

इस दिन एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 35 किसानों ने भाग लिया। 'फार्म प्रबंधन और बहीखाता' विषय पर आधारित इस प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारियों ने कृषि, बागवानी, पशु पालन, कृषि विपणन व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रिकॉर्ड रखने के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को बताया कि फार्म प्रबंधन में आय-व्यय का लेखा-जोखा लिखित रूप में रखना कितना आवश्यक है, जिससे खेती में आर्थिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। परियोजना द्वारा कुल्लू और लाहौल में अब तक कुल 21 उप-परियोजनाओं का चयन किया जा चुका है, जिनमें लघु सिंचाई विकास से खेतों तक पानी पहुंचाने, कृषि प्रसार व विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, कृषि विपणन और संस्थागत विकास के क्षेत्रों में कार्य हो रहा है।

सरकाघाट में बग्गी पोंटा सिंचाई योजना का निरीक्षण

सरकाघाट। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधक इकाई, सरकाघाट द्वारा निर्मित की जा रही उठाऊ सिंचाई परियोजना बग्गी पोंटा का निरीक्षण खंड परियोजना प्रबंधक, अश्वनी कुमार और कृषक विकास संघ के सदस्यों द्वारा किया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई सुविधा को बढ़ाना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। परियोजना में 58 लाख रुपये की लागत आई है और इसका कमांद क्षेत्र 10 हेक्टेयर है। इस सिंचाई परियोजना के बनने से क्षेत्र के 62 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कृषि आधारित आय में वृद्धि की उम्मीद है। खंड परियोजना प्रबंधक अश्वनी कुमार ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और इसे नवंबर महीने के अंत तक कृषक विकास संघ को सौंप दिया जाएगा। परियोजना के समर्पण के साथ, स्थानीय किसान फसल विविधीकरण में रुचि दिखा सकेंगे और अधिक उत्पादकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सोई कुहल के निर्माण कार्य का पीएमसी विशेषज्ञ द्वारा लिया जायजा

पालमपुर। 24 अक्टूबर, 2024 को प्रवाह सिंचाई योजना सोई कूहल में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए पीएमसी विशेषज्ञ ने दौरा किया।

इस उप-परियोजना को हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (एचपीसीडीपी) के तहत बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार करना है।

यह परियोजना 31.64 हेक्टेयर की कमांद क्षेत्र को कवर करती है और 119 किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी।

इस उप-परियोजना के लिए 75.82 लाख रुपये का निर्माण कार्य 3 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था और वर्तमान में यह कार्य तेजी से चल रहा है। निरीक्षण के दौरान, विशेषज्ञों ने निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी काम मानक और प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहे हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञों ने क्षेत्र के किसानों से संवाद किया, ताकि उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को समझा जा सके।

इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है।

सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी के साथ, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।

17.73 हेक्टेयर भूमि के लिए नई सिंचाई सुविधा

ऊना। खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई ऊना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसाल में निर्मित हो रही सिंचाई परियोजना खाजा का निरीक्षण खण्ड परियोजना प्रबंधक, डॉ. गुलशन मनकोटिया द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय कृषक विकास संघ के सदस्यों और अन्य सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई।

डॉ. मनकोटिया ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि इस उप परियोजना में ट्यूबवैल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 17.73 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे लगभग 30 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना का कुल खर्च लगभग 62 लाख रुपये आंका गया है। उन्होंने बताया कि शेष कार्य की टेंडर प्रक्रिया जारी है और जल्द ही पानी वितरण का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस परियोजना को कृषक विकास संघ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

नोगी खड्ड सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करके कृषक विकास संघ को सौंपी

मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के दूसरे चरण के तहत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी द्वारा गोहर खंड के अंतर्गत नोगी खड्ड से काण्डलु सिंचाई परियोजना का निरीक्षण जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. हेम राज वर्मा के द्वारा किया गया। इस सिंचाई परियोजना के बनने से 11.84 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा हो रही है, जिससे क्षेत्र के 130 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस सिंचाई परियोजना को बनाने में कुल खर्चा लगभग 28 लाख रुपये आया। निरीक्षण के दौरान एक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिंचाई परियोजना को आधिकारिक तौर पर कृषक विकास संघ (केवीए) को सौंपा गया और किसानों को अपने कृषि कार्यों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को परियोजना के मापदंडों से अवगत कराना और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस कार्यक्रम में 35 किसानों ने भाग लिया जिसमें मटर की खेती पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान किसानों को फसल विविधीकरण के लाभ, नक्दी फसलों की खेती की संभावनाएं, और सिंचाई चैनल के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मण्डी के अन्य अधिकारी भी शामिल थे।

कृषि विकास के लिए अभिविन्यास और आवश्यकता मूल्यांकन शिविर

चम्बा। 10 अक्तूबर 2024 को खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई चम्बा ने सिंचाई परियोजना रिट्टा उरला में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई चम्बा के सदस्य बाबर अली (कृषि विकास अधिकारी), साहिल पठानिया (कृषि विस्तार अधिकारी) और राधिका कपूर (कृषि अधिकारी) ने भी भाग लिया। इस प्रकार, यह शिविर न केवल किसानों को आवश्यक जानकारी देने में सहायक रहा, बल्कि उनके कृषि कार्यों को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ।

शिविर का मुख्य विषय 'अभिविन्यास और आवश्यकता मूल्यांकन' था, जिसमें 26 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को मटर और पालक के बीज भी वितरित किए गए। इस सिंचाई परियोजना के निर्माण से लगभग 6.03 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 18 लाख रुपये है, जिससे 57 किसान परिवारों के 262 किसानों को लाभ होगा। प्रशिक्षण शिविर में, कृषि अधिकारियों ने परियोजना की गतिविधियों से किसानों को अवगत कराया और उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। लाभार्थियों को दिए गए बीजों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

मुरंग नाला सिंचाई योजना कृषक विकास संघ को सौंपे जाने की तैयारी में

रामपुर। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन के अंतर्गत खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, रामपुर की सिंचाई परियोजना मुरंग नाला कारबा के निर्माण में लगभग 50 लाख रूपये की लागत से तैयार किया जा रहा जिसका 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस सिंचाई परियोजना से लगभग 14.13 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा जिससे 60 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। खण्ड परियोजना प्रबंधक डॉ. प्रवीण अत्री के साथ कृषक विकास संघ के सदस्यों ने परियोजना का दौरा किया तथा ठेकेदार को कूहल का काम निर्धारित समय पर समाप्त करने का निर्देश दिये। गांव में एक दिवसीय शिविर का आयोजना भी किया गया जिसमें सब्जियों के बीज बांट कर किसानों को पारंपरिक खेती से हट कर सब्जियों की ओर रुख करने की गुजारिश की। इस मौके पर परियोजना द्वारा गांव के सभी किसानों को उपकरण पेटी भी मुहैया करवाई गई। साथ ही परियोजना में चल रही अन्य गतिविधियों तथा योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत करवाया गया ताकि अधिक से अधिक परिवार परियोजना का लाभ उठा सकें।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में डॉ. सुनील चौहान, परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
प्रधान संपादक: डॉ. सुनील चौहान, परियोजना निदेशक। सलाहकार संपादक: राजेश्वर ठाकुर। फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com
संपादक: डॉ. जगदीश जंजीहा, विषय-विशेषज्ञ (सूचना-शिक्षा-संचार)। सम्पादकीय सहयोग: ज्योति ठाकुर, शालभ ठाकुर और अंकुश पटियाल। सूचना-शिक्षा-संचार परामर्श: सुशील कुमार शर्मा।